

Written by मेरी बटिया संवाददाता  
Tuesday, 10 July 2018 00:56

: 000000 000000 00000000 00000000 000 0000000000 00 00000000 000000 00 0000000000  
00 0000 :000000, 00000000, 00000000000000 0000 0000 **27** 00000000 000000 0000 00  
0000000000 00 0000 0000 :00000 00 0000000000 00000 00 0000000000 0000 000000  
0000000000 00000 0000 00000000-000000 00000 :

0000 00000000 000000000000

00 00000000 :सू त्री-खतना की परम् परा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज गहरी चिंता जतायी है। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में अबोध लड़कियों के मादा जननांग वधितन की परम् परा पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह परम् परा लड़की के शारीरिक "अखंडता" का उल्लंघन करता है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉरनी जनरल के के.वेणुगोपाल को केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया कि यह अभ्यास लड़की बच्चों के अपूरणीय नुकसान पहुंचाता है और उन्हें प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।

[00000 00 000000 00 00000000 0000000000 00, 000000 00 00000 00000](#)

उन्होंने खंडपीठ को बताया, जिसमें जस्टिस 00 00 म खानवलिकर और डीवाई चंद्रचुद भी थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और लगभग 27 अफ्रीकी देशों जैसे देशों ने इस अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुस्लिम समूह के लॉ उपस्थिति वरिष्ठ वकील 00 00 म सधिवी ने कहा कि मामला संवैधान बेंच को संदर्भित किया जाना चाहिए क्योंकि यह धर्म की आवश्यक अभ्यास के मुद्दे से संबंधित है जिसे जांचने की आवश्यकता है।

खंडपीठ ने कहा, "00 कव्यक्ति की शारीरिक अखंडता धर्म और उसके आवश्यक अभ्यास का हिस्सा क्यों होनी चाहिए," इस अभ्यास ने 00 कलड़की के शरीर के "अखंडता" का उल्लंघन किया। "किसी और का नयित्रण क्यों होना चाहिए 00 कव्यक्ति की जननांगों पर, "यह कहा संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, वेणुगोपाल ने केंद्र के रुख के दोहराया और कहा कि इस अभ्यास ने बालक के विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया और इसके अलावा, इस तरह के जननांग वधितन के उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।

0000 00000000 00000 00000000 00000000 00 00000000 000000, 00 00000000-000000 00 0000000000  
000000000000 00000000 000000 0000 00 00000000 00000000 000000 00 000000 00000000 :-

[000000 00 00000 00 00000 00 00000000 00 000000](#)

दूसरी ओर सधिवी ने इस्लाम में पुरुष खतना (खटना) के अभ्यास को संदर्भित किया और कहा कि सभी देशों में इसकी अनुमति है और यह स्वीकार्य धार्मिक अभ्यास है और सुनवाई स्थगित करने की मांग की गई है। खंडपीठ ने अब पीआईएल तय कर दी है 16 जुलाई को सुनवाई के मुद्दे पर वकील सुनीता तिवारी ने दायर किया। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने केरल और तेलंगाना के पीआईएल के पक्ष बनाने का आदेश दिया था, जिसने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालग लड़कियों की महिला जननांग उत्परिवर्तन के अभ्यास को चुनौती दी है। इसने आदेश दिया कि केरल और तेलंगाना जैसे राज्य, जहां बोहरा मुस्लिम समुदाय रहते हैं, को मुकद्दमेबाजी के पक्ष भी बनाया जाना चाहिए। और उन्हें भी नोटिस जारी करना चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में पहले से ही राज्य है।

अदालत ने 8 मई को दिल्ली स्थित वकील सुनीता तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने पर सहमत व्यक्ति की थी कि महिला जननांग उत्परिवर्तन का अभ्यास "बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील" था। उसने नोटिस जारी की थी और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के अलावा महिला और बाल विकास सहित चार केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा था, जहां शिया मुस्लिम हैं, दाऊदी बोहरा मुख्य रूप से रहते हैं। तिवारी ने अपनी याचिका में केंद्र और राज्यों को देश भर में 'खटना' या "मादा जननांग उत्परिवर्तन" (फजीम) के अमानवीय अभ्यास पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। "

याचिका ने फजीम को अपराध बनाने की दशा मांगी है जिस पर कानून परिवर्तन जैसे कि जेंसियां को स्वयं पर संज्ञान ले सकती है। इसने कठोर सजा के प्रावधान के साथ अपराध को "गैर-संगत और गैर-जमानती" बनाने की भी मांग की है। कानून और न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय को याचिका के पक्ष भी दां ग है, जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सम्मेलनों को संदर्भित करते हैं, जिन पर भारत हस्ताक्षर करता है। याचिका में कहा गया है कि मादा जननांग उत्परिवर्तन के अभ्यास के परिणामस्वरूप पीड़ितों के बुनियादी मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन हुए हैं, जो इन मामलों में नाबालग है। फजीम "अवैध रूप से लड़कियों (पांच साल के बीच और युवावस्था प्राप्त करने से पहले) पर" अवैध रूप से "किया जाता है और" बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक घोषणा के खिलाफ है, भारत भारत को हस्ताक्षर करता है ", याचिका ने कहा, इस अभ्यास को "कलड़के के शरीर के लार्थि स्थायी रूप से अक्षमता" के कारण जोड़ा गया।

[□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□](#)

"खटना 'या' फजीम 'या' खपट्ट का अभ्यास लोगों के बीच असमानता पैदा करने और महिलाओं के प्रति भेदभाव करने के लिए भी है। चूंकि यह नाबालगों पर किया जाता है, इसलिए यह बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का भी उल्लंघन करता है क्योंकि यहां तक कि नाबालग याचिका में कहा गया है कि व्यक्ति की सुरक्षा, गोपनीयता का अधिकार, शारीरिक अखंडता और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार से स्वतंत्रता का अधिकार है। "यह किसी भी चिकित्सा कारण के बिना दाऊदी बोहरा धार्मिक समुदाय के भीतर हर लड़की के बच्चे पर कानून से अनुष्ठान किया जाता है और कुरान में कोई संदर्भ नहीं है। यह बच्चे और मानवाधिकारों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का भी उल्लंघन करता है और 1996 के अवैध आप्रवासन सुधार और आप्रवासी उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून का अपराध है और अब ऑस्ट्रेलिया और कुछ में अपराध अन्य देशों के साथ ही, "यह दावा किया भारत में अवैध कानून घोषित करने के लिए फजीम या खटना पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानून नहीं है। "

□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ :-

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

Written by मेरी बटिया संवाददाता  
Tuesday, 10 July 2018 00:56

---

[□□□□](#)